फोनः-4103333, 2362400 फैक्सः-0141-2373513 वर्षः 76 संख्याः 29 प्रभात जयपुर, शनिवार 30 अगस्त, 2025 डाक पं.सं. जयपुर सिटी/001/2021-23 पृष्ठ 8 मूल्य 2.75 रु.

ARBiT

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

Rashtradoot

Metro

epaper.rashtradoot.com

A Home In Time

In those years, Jaipur didn't feel like a city-it felt like a large, extended household, a house with open doors, ready chairs, and a memory for names.

The Amul Girl

Energy Drinks! No!

Energy Drinks may drastically impair Muscle Repair and Growth.

गहलोत की भांति सी.पी. जोशी भी अब राहुल गांधी के नज़दीक जाने की भरसक कोशिश कर रहे हैं

जोशी का मन्तव्य है, कि वे प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा का पद प्राप्त कर लें

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 29 अगस्त। अशोक गहलोत के नक्शे-कदम पर चलते हुए, सी.पी. जोशी भी राहुल गांधी की नाराज़गी के बाद खुद को फिर से कांग्रेस की मुख्यधारा में स्थापित करने के लिए जी-जान से जुटे हैं।

सी.पी. जोशी ने राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी (आरपीसीसी) के अध्यक्ष पद के लिए अपनी दावेदारी पेश कर दी है, जिससे उनके गोविंद सिंह डोटासरा की जगह लेने की चर्चा तेज हो गई है।

लेकिन उन्होंने यह रास्ता कैसे चुना?

जोशी ने मणिकम टैगोर (लोकसभा सांसद, तमिलनाडु) से संपर्क साधा है, जो राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं। और मणिकम के जरिए, जोशी की संपर्क की डोर पहुंची के.सी. वेणुगोपाल तक - जो इस वक्त राहुल गांधी की आवाज़ और अंत:करण माने जाते हैं, और कुछ विश्लेषकों के अनुसार, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी अधिक प्रभावशाली हैं।

- इस मन्तव्य की प्राप्ति के लिये जोशी ने तमिलनाडु से निर्वाचित कांग्रेस के सांसद टैगोर को माध्यम बनाया है। जैसा कि विदित ही है, टैगोर, राहुल गांधी के विश्वास पात्रों की सूची में काफी उच्च स्थान रखते हैं।
- टैगोर के जरिये जोशी, के.सी. वेणुगोपाल के नज़दीक पहुंचे हैं, और वेणुगोपाल ने उन्हें (सी.पी. जोशी को) पंजाब में जिलाध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया में पर्यवेक्षक नियुक्त करवा दिया है।
- वेणुगोपाल अब प्रचारित कर रहे हैं, कि हालांकि, जोशी ने केन्द्र व राज्य सरकार में वरिष्ठ पदों पर नियुक्ति पाई है, पर वे जानते हैं, कि यह राहुल गांधी का विश्वास है कि, योग्य व निष्ठावान जिलाध्यक्ष की नियुक्ति से पार्टी पुनर्जीवित होगी, इसलिए जोशी ने पंजाब के एक जिले के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिये गठित समिति में पर्यवेक्षक का छोटा सा पद स्वीकार किया है।
- वेणुगोपाल द्वारा सी.पी. जोशी के पक्ष में दिये गये इस सार्वजनिक सर्टिफिकेट से सी.पी. जोशी का पार्टी में रुतबा तो जरुर बढ़ेगा, पर क्या यह सी.पी. जोशी की पुनर्वास यात्रा में पहला कदम माना जा सकता है।

हाल ही में सी.पी. जोशी को पंजाब के एक जिला अध्यक्ष के चुनाव/चयन के लिए पर्यवेक्षक बनाया गया है- जो राहुल गांधी की एक नई और महत्वाकांक्षी योजना है, और जिसे वे काफी गंभीरता से ले रहे हैं। उनका मानना है कि कांग्रेस की वापसी की राह जिला अध्यक्षों के माध्यम से ही संभव है।

दिलचस्प यह है कि पंजाब में ज़िला अध्यक्षों की नियुक्ति पर पर्यवेक्षकों की हालिया बैठक में वेणुगोपाल ने सी.पी. जोशी की खुलकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि जोशी ने केंद्र और राजस्थान में कई वरिष्ठ पदों पर कार्य किया है, लेकिन इसके बावजूद वे एक साधारण ज़िले के पर्यवेक्षक का जिम्मा लेने से नहीं हिचकिचाए- सिर्फ इसलिए क्योंकि यह राहुल गांधी की प्रिय परियोजना है।

इसे वेणुगोपाल की ओर से "हार्ड सेल" (जोरदार सिफारिश) कहा जा सकता है, जिसमें वह राहुल को यह जताने की कोशिश कर रहे हैं कि जोशी जैसे बड़े नेता ने इतनी छोटी ज़िम्मेदारी को सिर्फ राहुल के लिए स्वीकार किया है।

बेहद दिलचस्प बात यह है कि सी.पी. जोशी कभी राहुल गांधी के करीबी माने जाते थे, जब वे एआईसीसी में 11 राज्यों के प्रभारी महासचिव थे। लेकिन समय के साथ उनके काम पर बढ़ती शिकायतों और अपेक्षित परिणामों की कमी के कारण राहुल ने उन्हें पद से हटा दिया।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'क्या रजिस्ट्री को रिट याचिकाओं की योग्यता (मेंटेनेलिबिटी) तय करने का अधिकार है?'

- यादवेन्द्र शर्मा -

जयपुर, 29 अगस्त। राजस्थान हाईकोर्ट ने जगदीश प्रसाद शर्मा द्वारा दायर एक रिट याचिका पर हाईकोर्ट की रजिस्ट्री द्वारा "मेंटेनेबिलिटी" (किसी मामले की सुनवाई के योग्य होना) को मुद्दा बनाते हुए याचिका को दायर होने से रोकने के खिलाफ कठोर टिप्पणी करते हुए आदेश पारित किए कि 1 सितम्बर 2025 को दोपहर 2 बजे राजस्थान हाईकोर्ट की बार इस मुद्दे पर अपने तर्क और मत प्रस्तुत करें।

- हाईकोर्ट ने इसी मुद्दे पर कई शिकायतें दर्ज किए जाने के कारण हाईकोर्ट बार एसोसिएयेशन के सभी सदस्यों को अपना तर्क और मत प्रस्तुत करने के लिए एक सितम्बर को दोपहर 2 बजे अदालत में आमंत्रित किया है।

न्यायाधीश समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश जगदीश प्रसाद शर्मा द्वारा दायर रिट याचिका सुनवाई करते हुए दिए।

इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से सुनील समदड़िया ने अदालत के समक्ष यह आपत्ति प्रस्तुत की थी कि हाईकोर्ट की रजिस्ट्री स्वत: ही आदेश पारित करती है कि कई रिट याचिकाऐं

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

द्वितीय विश्व युद्ध से प्रचलित "ग्लोबलाइज़ेशन" का युग जर्जर हालात में है

पुतिन, शी जिनपिंग व मोदी इस खंडहर होते "सिस्टम" को अपने -अपने नज़रिये से देख रहे हैं, पर तीनों एकमत हैं, अमेरिका की दादागिरी के खिलाफ

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 29 अगस्त। अन्तर्राष्ट्रीयकरण जिसे कभी 21वीं सदी की ऐसी लहर माना जाता था, जिसे रोका नहीं जा सकता, अब अचानक अपने सबसे कठिन परीक्षण से गुजर रहा है। डॉनल्ड ट्रंप की सत्ता में वापसी और उनके टैरिफ (शुल्क) आक्रमण ने न केवल वित्तीय बाजारों को अस्थिर कर दिया है, बल्कि दुनिया के तीन सबसे प्रभावशाली नेताओं - व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग और नरेन्द्र मोदी - की ओर से एक स्वर में प्रतिरोध को भी जन्म दिया है। इन तीनों की प्रतिक्रिया अलग-अलग रही है, लेकिन संयुक्त रूप से वे वॉशिंगटन की एकतरफा नीति को खारिज करते हैं और एक नए व्यापारिक व्यवस्था की रूपरेखा की ओर संकेत करते हैं।

ट्रंप द्वारा पुराने सिस्टम को तोड़ना पुतिन की नज़र में कोई संकट नहीं, बल्कि एक अवसर है। रूसी नेता ने इस ओर इशारा किया है कि प्रतिबंधों और भू-राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के बावजूद अमेरिका के साथ व्यापार वास्तव में ट्रंप के शासनकाल में बढ़ा है। उनके अनुसार, अमेरिका की संरक्षणवादी नीति अमेरिकी प्रभुत्व में कमी की दर को तेज करती है। इससे रूस को चीन के साथ नजदीकी बढ़ाने, ऊर्जा निर्यात को विस्तार देने और वैश्विक अस्थिरता का रणनीतिक लाभ उठाने का अधिक अवसर मिलता है। मॉस्को पुराने नियमों के टूटने का शोक नहीं मना रहा; वह इस मैदान, जिस पर अमेरिका का प्रभुत्व कम है, पर खेलने का मौका स्वागत करता है।

दूसरी ओर शी जिनपिंग ने इस क्षण को अन्तर्राष्ट्रीयकरण के रक्षक के रूप में खुद को प्रस्तुत करने का मौका बनाया है। वे चेतावनी देते हैं कि "ट्रेड वॉर का कोई विजेता नहीं होता" और संरक्षणवाद केवल दूसरों को ही नहीं, बल्कि अमेरिका को भी नुकसान पहुंचाता है। एक के बाद एक भाषणों में, शी ने यूरोप, एशिया और ग्लोबल साउथ से अमेरिका की आर्थिक 'दादागिरी' का

- पुतिन, इस "सिस्टम" के टूटने से उत्पन्न अव्यवस्था को एक सुअवसर मानते हैं, अमेरिकी दादागिरी वाले सिस्टम में, खुल कर खेलने का आनन्द लेना चाहते हैं।
- चीन अपने आप को पुराने ग्लोबलाइज़ेशन का विरोध करता नहीं दिखाना चाहता, पर नए सिस्टम को अमेरिका उन्मुख नहीं, बल्कि, चीन के नेतृत्व वाला सिस्टम बनाना चाहता है।
- नरेन्द्र मोदी, इस घटनाक्रम में, नेतृत्व करने की महत्वाकांक्षा नहीं रखते, बल्कि अपनी स्वायत्तता, (ओटोनोमी) की सुरक्षा चाहते हैं, जिससे अपने बारे में स्वयम् निर्णय लें, उन्हें किसी के दबाव में निर्णय नहीं लेना पड़े।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मतदाता सूची पुनरीक्षण की संभावना से तृणमूल में भय पसरा

पर यह कवायद भाजपा के लिए भी नुकसान देह हो सकती है

- जाल खंबाता -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 29 अगस्त। चुनाव आयोग द्वारा बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की शुरुआत करने के निर्णय से पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल में चिंता की लहर दौड़ गई है। यहां भी यह प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को आशंका है कि यह कवायद प्रवासियों की नागरिकता और मतदान अधिकारों के मुद्दे पर राजनीतिक तूफान खड़ा कर सकती है।

आयोग के निर्देशों के अनुसार, मतदाताओं को अपनी पात्रता साबित करने के लिए 12 निर्धारित दस्तावेजों में से कोई एक पेश करना होगा। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने बाद में आदेश दिया कि आधार कार्ड और पुराने मतदाता पहचान पत्र भी मान्य माने जाएं, लेकिन ज़मीनी रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि पश्चिम बंगाल के लगभग एक करोड़ निवासियों के पास संभवतया आवश्यक दस्तावेज नहीं हैं।

- मतदाता सूची पुनरीक्षण से, 1947 से 1971 के बीच भारत आए बांग्लादेशी प्रभावित हो सकते हैं और महत्वपूर्ण बात है कि इनमें से 98 प्रतिशत हिंदू हैं।
- कुछ राजनैतिक विशेषज्ञ मतदाता सूची पुनरीक्षण को राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए सीधा राजनैतिक हमला बता रहे हैं, क्योंकि, इस हमले में उनका कोर वोट बैंक प्रभावित हो सकता है।
- ग्राउण्ड रिपोर्ट्स कहती हैं कि प. बंगाल के एक करोड लोगों के पास अभी भी आवश्यक दस्तावेज नहीं हैं।

इससे तृणमूल खेमे में गहरी चिंता व्याप्त है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को अपने चुनाव प्रचार का मुख्य आधार बनाने की तैयारी में दिख रही है। भाजपा लंबे समय से बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ का आरोप लगाती रही है और दावा करती है कि बंगाल की मतदाता सूची में बडी संख्या में ऐसे नाम हैं जिनकी जांच जरूरी है।

भाजपा के नीतिकारों का मत है कि मतदाता सूची के पूनरीक्षण के माध्यम से भाजपा खुद को राष्ट्रीय सुरक्षा और जनसंख्या संतुलन के रक्षक के रूप में पेश कर मतदाताओं को आकर्षित कर सकती है।

वहीं, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए यह प्रक्रिया एक प्रत्यक्ष राजनीतिक

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

दिसम्बर में पुतिन भारत आयेंगे

मॉस्को, 29 अगस्त। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिसंबर में भारत आएंगे। क्रेमलिन ने इसकी पुष्टि कर दी है। इससे पहलेसोमवार को चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन की मुलाकात होगी। यह जानकारी शुक्रवार को क्रेमलिन के विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव ने दी।

- वे भारत में वार्षिक द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे।

अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने पर भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगाया था। इसे लेकर रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी को फोन किया था। इस दौरान पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को इस साल के अंत में वार्षिक द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में भारत आने का न्योता दिया था। अब क्रेमलिन ने इस पर मुहर लगा दी है। क्रेमलिन के विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव ने कहा कि पुतिन दिसंबर में भारत की यात्रा करेंगे।

2020 में हिंसात्मक संघर्ष के बाद में भारत व चीन के सम्बंधों में बदलाव कैसे आया?

न्यूज़ एजेन्सी ब्लूमबर्ग के अनुसार, चीन के राष्ट्रपति शी ने भारत की राष्ट्रपति मुर्मू को गोपनीय पत्र लिखकर चीन -भारत सम्बंधों में सुधार लाने का प्रयास शुरु कर दिया था

- जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 29 अगस्त। चीनी लोग कूटनीति में माहिर माने जाते हैं। इसका उदाहरण शी जिनपिंग की उस गुप्त चिट्ठी से मिला जिसमें उन्होंने भारत से रिश्ते सुधारने की पहल की।

एक अज्ञात भारतीय अधिकारी के हवाले से आई एक रिपोर्ट के अनुसार, शी जिनपिंग का पत्र यह परखने के लिए था कि भारत, चीन के साथ अपने रिश्तों को फिर से संतुलित करने के लिए तैयार है या नहीं।

जब इस साल की शुरुआत में अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने चीन पर व्यापारिक दबाव बढ़ाया, तो बीजिंग ने भारत तक पहुँच बनाने के लिए राष्ट्रपति शी जिनपिंग का एक निजी पत्र राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजा। यह दावा न्यूज़ एजेन्सी ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में किया गया।

- ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, इस पत्र के पश्चात् जून महीने के बाद भारत ने चीन के साथ सम्बंध सुधारने की पहल को गंभीरता से लेना शुरु किया।
- ट्रंप द्वारा बार-बार, यह दम्भ भरने से, कि उन्होंने भारत-पाक के युद्ध को अपने प्रयास से खत्म करवाया, ने दोनों देशों को और नजदीक आने में मदद की।
- और, चीन ने यह नारा दिया कि, "हाथी व ड्रैगन" को मिलकर नृत्य करने के अलावा कोई और, समझदारीपूर्ण विकल्प नहीं है।

हालाँकि पत्र राष्ट्रपति मुर्मू को भेजा गया था, लेकिन संदेश जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुँचा दिया गया। उस नोट में शी ने चिंता जताई थी कि अमेरिका और भारत के बीच होने वाले किसी भी समझौते से बीजिंग के हितों को नुकसान पहुँच सकता है। रिपोर्ट में कहा गया कि चीन ने एक प्रांतीय अधिकारी का भी नाम बताया था जो बीजिंग की पहल को आगे बढ़ाएगा।

रिपोर्ट के अनुसार, जून से मोदी सरकार ने चीन की इस पहल को गंभीरता से लेना शुरू किया। उसी समय भारत अमेरिका से भी ट्रंप की टैरिफ धमकियों और उनकी इस दलील पर बातचीत कर रहा था कि जम्मू-कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले (जिसमें 26 लोग मारे गए) के बाद भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव कम कराने में उन्होंने (ट्रंप ने) भूमिका निभाई।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ब्लूटूथ से नकल कराने वाले आरोपी को जमानत नहीं मिली

जयपुर, 29 अगस्त। अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-1, महानगर द्वितीय ने राजस्व अधिकारी और अधिशाषी अधिकारी भर्ती, 2022, में परीक्षार्थियों को ब्लूटूथ के जरिए नकल कराने के मामले में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे

- आरोपी राजस्व अधिकारी व अधिशाषी अधिकारी परीक्षा 2022 के मामले में न्यायिक अभिरक्षा में है।

आरोपी तुलछाराम कालेर को जमानत देने से इन्कार कर दिया है। पीठासीन अधिकारी बीएल चंदेल ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी के कृत्य से योग्य व्यक्ति चयन से वंचित हुए हैं और मेहनत करने वाले हजारों अभ्यर्थियों के साथ धोखाधड़ी कर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। ऐसे में आरोपी को जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता।

जमानत अर्जी में कहा गया कि उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है और वह

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

गहलोत प्रदेश के हर बड़े-छोटे मुद्दे पर बयान देते हैं, पर एस.आई. भर्ती परीक्षा 2021 रद्द किए जाने के फैसले पर चुप्पी क्यों?

क्या यह चुप्पी गहलोत की असमंजता को दर्शाती है क्योंकि उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल में पेपरलीक से निपटना तो दूर, बल्कि उसे बढ़ावा दिया गया?

- यादवेन्द्र शर्मा -

जयपुर, 29 अगस्त। राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा एस.आई. भर्ती परीक्षा-2021 को रद्द करने के आदेश को लेकर विपक्ष और पक्ष के नेताओं में मीडिया में काफी बयानबाजी चली। एक तरफ भाजपा नेता जैसे, किरोड़ी लाल मीणा, ने फैसले को सराहा और इसे उनकी और भाजपा की राजनीति में जीत बताया, वहीं विपक्षी नेताओं ने परीक्षा रद्द नहीं करने के राज्य सरकार के फैसले पर उंगली उठाई। पर इन सभी बयानों में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की चुप्पी सबसे ज्यादा स्पष्ट नजर आई, उन्होंने इस विषय पर एक ट्वीट भी नहीं दिया।

न्यायाधीश समीर जैन के फैसले में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी और अवलोकन यह था कि व्यापक पेपरलीक और नकलबाजी के अपराध को राजस्थान लोक सेवा आयोग (आर.पी.एस.सी.) सदस्यों की मिलीभगत के बिना अंजाम नहीं दिया जा सकता। न्यायाधीश समीर जैन के फैसले में यह भी कहा गया कि इस मामले की गहन जांच से स्पष्ट होता है कि आर.पी.एस.सी. द्वारा आयोजित परीक्षाओं में कई तरीके की त्रुटियां थी, जिन्हें जानबूझकर नज़रअंदाज किया गया था और अपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था। अदालत ने अपने आदेश में हिन्दी मुहावरा "घर का भेदी-लंका ढाए" का उपयोग करते हुए निष्कर्ष दिया कि आर.पी.एस.सी. अधिकारी, जिनमें बाबूलाल कटारा, रामूराम रायका, मंजू शर्मा, संगीता आर्या और जसवंत राठी शामिल थे, ने मिल-जुलकर पेपरलीक की वारदात को अंजाम दिया।

इस मामले में अदालत ने अपने आदेश पर इस बात पर भी हैरानी जताई है कि बाबूलाल कटारा कई पेपरलीक जैसे, ग्रेड-2 टीचर भर्ती-2022 और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा-2022 में भी एफ.आई.आर. में नामजद थे और एफ.आई.आर. में दर्ज तथ्यों को देखते हुए आर.पी.एस.सी. ने इन परीक्षाओं को रद्द किया था। परन्तु आर.पी.एस.सी. या राज्य सरकार ने किसी भी स्तर पर बाबूलाल कटारा को आर.पी.एस.सी. सदस्यता से हटाने या उनके खिलाफ कार्रवाई आरम्भ करने के विषय में न तो सोचा और न ही कोई कदम उठाया।

एस.आई. भर्ती परीक्षा-2021 में पेपरलीक मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की चुप्पी, इसलिए भी ज्यादा चुभती है कि, क्योंकि न्यायालय में जिन आर.पी.एस.सी. सदस्यों को साजिश में भागीदार बताया है, उनमें से कम से कम दो सदस्यों के चयनित होने पर गहलोत सरकार के कार्यकाल के दौरान भी कई तरह की चर्चा हुई थी।

पहला नाम संगीता आर्य का है, जो

- हाईकोर्ट का निर्णय इस तथ्य पर जोर देता है कि व्यापक पेपरलीक को आर.पी.एस.सी. सदस्यों की मिलीभगत के बिना अंजाम नहीं दिया जा सकता था। बल्कि आर.पी.एस.सी. सदस्य न केवल परीक्षा प्रक्रिया की त्रुटियों को जानते थे, बल्कि जानबूझकर अनदेखा कर रहे थे ताकि अयोग और कपटी तरीकों से अभ्यर्थियों का चयन किया जा सके।
- इस प्रकरण में यह भी हैरान करने वाली बात है कि आर.पी.एस.सी. सदस्यों के नाम अन्य परीक्षाओं के पेपरलीक में भी नाम आए थे, और इन मामलों में दर्ज एफ.आई.आर. की बिसात पर पेपर रद्द कर दिए गए, परन्तु आरोपी सदस्यों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।
- पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत की चुप्पी इसलिए भी चुभती है क्योंकि उनके कार्यकाल में आर.पी.एस.सी. में नियुक्त किए गए दो सदस्यों का नाम बड़ा ही विवादों से घिरा रहा। एक था कुमार विश्वास की पत्नी मंजू शर्मा और दूसरा था गहलोत के करीबी और मुख्य सचिव रहे निरंजन आर्य की पत्नी संगीता आर्य। अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद इन नियुक्तियों के फैसले पर सवाल और भी प्रबल हो गये हैं।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पेपरलीक का ईनामी अपराधी उड़ीसा से गिरफ्तार

जयपुर, 29 अगस्त। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने कार्रवाई करते हुए विभिन्न पेपर लीक मामलों में पचास हजार के इनामी वांछित अपराधी को उड़ीसा से गिरफ्तार किया है।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एटीएस और एसओजी वीके सिंह ने

- एसओजी ने राजस्थान से 1600 किलोमीटर दूर फरार आरोपी को पकड़ने में सफलता पाई।

बताया कि एसओजी ने कार्रवाई करते हुए विभिन्न पेपर लीक मामलों में पचास हजार का इनामी वांछित अपराधी विनोद कुमार रेवाड (42) निवासी रेनवाल जिला जयपुर को सोलह सौ किलोमीटर दूर दसपल्ला जिला नयागढ़ (उड़ीसा) से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बचने के लिए आरोपी रेल्वे ब्रिज बनाने वाले ठेकेदार के पास वाहनों में डीजल भरने का काम कर रहा था।

सिंह ने बताया कि आरोपी पेपर लीक के विभिन्न प्रकरणों यथा

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)